[Shri P. M. Sayeed]

been eclipsed by the colossal tragedy on the eastern coast.

We do not have on Assembly; we are directly under the Central rule. Our smallness and our location might have been the reasons for the fact that nobody in authority from the centre or the mainland visited us in this hour of our need.

I am not saying this as a complaint or in anger. I am only saying this out of a feeling of helplessness and loneliness.

Whatever that may be, I request the Government, Sir, to urgently take some steps to help those people in that island.

Firstly, let there be a medical team. Also let there be more supplies of food articles not only grain Let there be supply of building material—cement, timber, tiles, lime, asbestos etc.

Secondly, please send some soil scientists. Let them test the soil and suggest something to make it fit for cultivation. Then, rush coconut seedlings, other seeds and fertilizers

Thirdly, please give them fishing boats and also two big boats so that inter-island traffic could be re-established. Now, not only the mainland but even we in the other island are helpless to help our brethren.

Sir, I hope the Government will take these measures. Let it not be said that those people who had survived the cruelty of nature were doomed by the inaction of men. Just because we are small and away, let us not be forgotten.

17.29 hrs.

(ii) ACCUMULATION OF STOCKS IN SOME SICK TEXTILE MILLS

श्री हकमचन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मै इस विषय को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने जा रहा हूं, अच्छा होता कि सम्बन्धित मंत्री भी यहां पर उपस्थित होते—इस बात का मुझे बहुत दुःख है ।

भारत सरकार ने देश की 103 कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया है । ये मिलें प्रतिवर्ष 42 करोड़ रुपये का घाटा देती जा रही है और यह घाटा दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है । इस का मूल कारण है कि इन मिलों के अन्दर टेक्नीकल लोग ज्यादा नहीं है, अफसर ज्यादा भर गये है, जिन्हें वस्तुस्थिति का कोई ज्ञान नही है और कपड़ा बेचने की जो पोलिमी है, जो वितरण व्यवस्था है, उस मे नानाप्रकार की त्रुटियां हैं । उसी का परिणाम है कि तमाम मिलों मे बहुत बड़ी मात्रा में कपडा जमा होता जा रहा है, जिस से सूजी जाम होती जा रही है । जब कि कोई भी कन्ट्रोल का कपडा मार्केट में मिलता नहीं है, आप दिल्ली शहर मे ही देख लीजिए कन्ट्रोल की धोती पहनने को नही मिलती है । यह स्थिति आज सारे देश मे है । ऐसा क्यों है ?

व्यापारी एन० टी० सी० की मिलों से कपड़े का सौदा करता है, लेकिन अगर दो पैसा बढ़ जाए तो जिस से सौदा किया होता है, उस का सौदा एन० टी० सी० द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दूसरे को माल दे दिया जाता है । अपनी बात के पक्के नही है, जिस से दलाल और व्यापारी दोनों उन से नाखुश है । कपडा बेचने मे इस तरह की और भी अनेकों त्रुटियों हैं, जिन में सुधार होना बहुत जरूरी है ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं—मध्य प्रदेश की कुछ मिलों ने कलकत्ता की एक पार्टी को कपडा बेचा—पार्टी का नाम है—राज लक्ष्मी एसोसियेट्स कलकत्ता—इन के साथ 50 लाख रुपये का सौदा हुआ, लेकिन इन से केवल 15 हजार रुपये डिपोजिट रखवाया । 50 लाख का कपड़ा बेच दिया और जब वह कलकत्ते पहुंच गया, तो उस व्यापारी ने उस कपड़े को लेने से इनकार कर दिया । महीनों हमारा कपड़ा वहां पड़ा रहा और इस में हमें काफी घाटा हुआ । उसने बिल्टी छुड़वाई नहीं और हमें डेमुरेज देना पड़ा और उस कपड़े को

ले कर वापस आना पड़ा, कुछ सस्ते दामों पर बेच दिया । ऐसी स्थिति है ।

इतनी ही नहीं बल्कि जो माल खरीदा जाता है, उस में भी नाना प्रकार की त्रुटियां है । कैमिकल का माल, काटन का माल या मशीनरी में लगने वाला जो सामान है, वह घटिया किस्म का लिया जाता है और पैसे ज्यादा दिये जाते हैं । ऐसे अनेक आप को उदाहरण मिलेंगे ।

इन मिलों के अन्दर कुछ मान्यता प्राप्त यूनियनें काम करती हैं लेकिन वे ठीक प्रकार से काम नही करती । मशीनें बन्द रहती है और पिछली सरकार की शरण मे चलने वाली मान्यता प्राप्त यूनियन जो हैं, उस के वर्कर और मैम्बर्स जो मिलों मे है काम नही करते और फौकट की तन्ख्वाह लेते है । अगर किसी मिल में 3 हजार आदमी काम करते हैं तो उन में से 500 ऐसे आदमी आप को मिलेंगे जो बिना काम करे वेतन लेते है । आप इसकी इन्क्वायरी करा कर पता लगा सकते है । चार साचों का समझौता हुआ था मान्यता प्राप्त यूनियनस से, लेकिन उन्ही मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा रद्द किया जा रहा है जिससे काफी मशीने बन्द रहती है और मिलो मे घाटा हो रहा है । मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सरकार ऐसी पालिसी बनाए जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले । जनता पार्टी की सरकार ने अधिक लोगों को रोजगार देने की बात कही है । अगर इन सब मिलों में चार शिफ्टें छः छः घंटे की चालू कर दी जायें, तो बहुत से लोगों को काम मिल जाएगा । मैं इस का विरोधी नही हूं । इस से उत्पादन भी अच्छा होगा परन्तु यूनियनों के झगड़े नाना प्रकार के हैं और हमारे जो आई० ए० एस० आफीसर्स हैं, वे उन को समझ नही पाते हैं जिस का परिणाम यह होता है कि आए दिन हड़ताल होती रहती हैं । जो यूनियनें पहले हड़ताल का विरोध करती थीं, आज वे विरोध में आने के कारण हर जगह उद्योगों में हड़ताल करवा रही हैं चाहे वह बम्बई हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो या मध्य प्रदेश हो, सो किसी भी प्रान्त की मिलें हों, हड़तालें हो रही हैं । इस से उत्पादन की क्षति होती है और तोड़फोड़ भी होती है । यह सारी स्थिति आज है । ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार का ध्यान खीचना चाहता हूं कि आज जो अफसर एन० टी० सी० में बैठे हुए हैं, वे अयोग्य हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप ने सुना होगा कि हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के श्री दीक्षित सेक्रेट्री हुआ करते थे । उन्होंने बहुत घपले किये है । और बहुत प्रकार का गबन किया है । उन को इस का डिप्टी चेयरमैन बना कर रखा है । मेरा कहना यह है कि जो टैक्नीकल आदमी है उन्हें काम सौंपा जाएं । टैक्नीकल लोगों को ढूढ कर ऐसे काम पर लगाया जाए और उन से यह काम लिया जाए और पुराने अधिकारियों को निकाला जाए । अगर ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है कि 103 मिलें जो देश के अन्दर है, वे अच्छी चलेंगी और उन को मुनाफा होगा ।

इस के अलावा वितरण में और माल के बेचने की व्यवस्था में सुधार हो और माल खरीदने में जो त्रुटियां हैं, उसे ठीक किया जाए । अगर मिलों के अन्दर सुधार होगा, तो मुनाफा होगा और प्रतिवर्ष जो घाटा बढ़ता जाता है वह नही होगा । अगर इसी तरह से घाटा बढ़ता रहा, तो यह एक बहुत बड़ा अभिशाप जनता सरकार पर होगा कि इतना घाटा हो रहा है । मैं समझता हूं कि मैंने जो चार शिफ्टों का सुझाव दिया है और अधिक लोगों को काम देने के लिए कहा है, उस पर सरकार ध्यान देगी और मेरे सुझावों को मानेगी ।

17.34 hrs.

(iii) ATTACK ON INDIAN EMBASSY OFFICIAL IN WASHINGTON

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not know whether any useful purpose will be served by my